The Asian Age 11 October, 2017

CENTRE PLANS TO SET UP MINI FOOD PARKS

New Delhi, Oct. 10: The government will focus on setting up of mini food parks to raise the processing level, Union minister Sadhvi Niranjan Jyoti said on Tuesday and asked the industry to buy agri items directly from farmers to boost their income.

Ms Jyoti, who is minister of state for food processing, said all 42 sanctioned mega food parks will be operational by 2019. She assured the industry that the ministry will consider and take up any of their concern related to GST.

Addressing a conference on FMCG, the minister said the government will facilitate setting up of 'mini food park' across the country on smaller land parcel to boost food processing level.

This will be done under the new ₹6,000 crore SAMPADA scheme approved by the government recently, she added.

The ministry provides subsidy of up to ₹50 crore to set up a mega food park. There is a need, Ms Jyoti said, to increase the food processing level to reduce wastage of farm produce.

The minister felt that farmers' income will not be doubled unless their produce is procured directly. The processing sector will also get their raw material at cheaper rates and better quality if they buy agri produce directly from farmers, she suggested. — *PTI*

Hari Bhoomi

11 October, 2017

उद्योगों को किसानों से सीधी खरीद करने को कहेगी

सरकार करेगी मिनी खाद्य पार्क की स्थापना

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज कहा कि सरकार खाद्य उपज के प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने के लिए मिनी खाद्य पार्कों की स्थापना करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। उन्होंने खाद्य उद्योगों से आग्रह किया कि वे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि जिंसों की सीधे उनसे करें। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मंजूर किये गये सारे के सारे मेगा फूड पार्क वर्ष 2019 तक परिचालन में आ जायेंगे। उन्होंने खाद्य उद्योग को आश्वासन दिया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इस उद्योग की माल एवं सेवा कर :जीएसटी: के संबंध में सभी तरह की चिंताओं पर विचार करने को तैयार है। तत्काल खपत उपभोक्ता माल :एफएमसीजी: पर एसोचैम के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए छोटे भूखंडों पर देश भर में 'मिनी फूड पार्क' की स्थापना के लिए सुविधायें प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा, सरकार के द्वारा हाल में मंजूर की गई 6,000 करोड़ रुपये की 'संपदा' योजना के तहत किया जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करता है।

■ सारे के सारे मेगा फूड पार्क वर्ष 2019 तक परिचालन में आ जायेंगे

उपज की रुकेगी बर्बादी

ज्योति ने कहा कि कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। मंत्री का मानना है कि किसानों की आय को तब तक दोगुना नहीं किया जा सकता है जब तक कि उपज की खरीद सीधे किसानों से न की जाए। मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षित खाद्य होने की भी आवश्यकता है।

अंशधारकों के लिए उदारता

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नियामक विभिन्न उत्पादों के लिए मानकों को लेकर सामने आती है जो वैश्विक स्तर पर मानकीकृत है जबकि कुछ विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई अंशधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मानकों में बदलाव करने के बारे में उदार विचार रखता है।

Rashtriya Sahara

11 October, 2017

उद्योगों को सीधे अपनी फसल बेच सकेंगे किसान

■ नई दिल्ली।

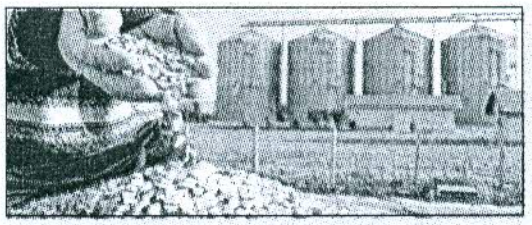

■ इसके लिए मिनी फूड पार्क स्थापित करेगी सरकार

■ उद्योगों को किसानों से सीधी खरीद के दिये जाएंगे निर्देश

■ वर्ष 2019 तक परिचालन में आ जाएंगे सभी फूड पार्क

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सरकार खाद्य उपज के प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने के लिए मिनी खाद्य पार्कों की स्थापना करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। उन्होंने खाद्य उद्योगों से आग्रह किया कि वे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि जिंसों की सीधे उनसे खरीद करें।

साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मंजूर किए गए सारे के सारे मेगा फूड पार्क वर्ष 2019 तक परिचालन में आ जाएंगे। उन्होंने खाद्य उद्योग को आश्वासन दिया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इस उद्योग की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में सभी तरह की चिंताओं पर विचार करने को तैयार है।

तत्काल खपत उपभोक्ता माल (एफएमसीजी) पर एसोचैम के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए छोटे भूखंडों पर देश भर में मिनी फूड पार्क की स्थापना के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि ऐसा, सरकार के द्वारा हाल में मंजूर की गई 6,000 करोड़ रुपए की संपदा योजना के तहत किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करता है। ज्योति ने कहा कि कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

मंत्री का मानना है कि किसानों की आय को तब तक दोगुना नहीं किया जा सकता है जब तक कि उपज की खरीद सीधे किसानों से न की जाए। मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सुरक्षित खाद्य होने की भी आवश्यकता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी :सीईओः पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में नियामक विभिन्न उत्पादों के लिए मानकों को लेकर सामने आती है जो वैश्विक स्तर पर मानकीकृत है जबकि कुछ विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई अंशधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मानकों में बदलाव करने के बारे में उदार विचार रखता है।■ भाषा

Jansatta 11 October, 2017

खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाने के लिए मिनी फूड पार्क खोलेगी सरकार

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को कहा कि सरकार खाद्य उपज के प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने के लिए मिनी खाद्य पार्कों की स्थापना करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने खाद्य उद्योगों से आग्रह किया कि वे किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि जिसों की खरीद सीधे उनसे करें।

साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मंजूर किए गए सारे के सारे मेगा फूड पार्क 2019 तक परिचालन में आ जाएंगे। उन्होंने खाद्य उद्योग को आश्वासन दिया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इस उद्योग की माल व सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में सभी तरह की चिंताओं पर विचार करने को तैयार है।

तत्काल खपत उपभोक्ता माल (एफएमसीजी) पर एसोचेम के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए छोटे भूखंडों पर देशभर में 'मिनी फूड पार्क' की स्थापना के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा सरकार की ओर से हाल में मंजूर की गई 6,000 करोड़ रुपए की संपदा योजना के तहत किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए तक की सबसिडी देता है। ज्योति ने कहा कि कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाए जाने की जरूरत है। मंत्री का मानना है कि किसानों की आय को तब तक दोगुना नहीं किया जा सकता है जब तक कि उपज की खरीद सीधे किसानों से न की जाए। मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सुरक्षित खाद्य होने की भी जरूरत है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नियामक विभिन्न उत्पादों के लिए मानकों को लेकर सामने आती है जो वैश्विक स्तर पर मानकीकृत है जबकि कुछ विचाराधीन हैं।

Hindustan 11 October, 2017

मिनी खाद्य पार्क की स्थापना होगी

नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए मिनी खाद्य पार्क की स्थापना करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। उन्होंने उद्योगों से आग्रह किया कि वे कृषि जिंसों की खरीद सीधे किसानों से करें।